रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं : एसबीआई

चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी ने कहा- मौजूदा हालात में बदलाव से बचना बेहतर

नई दिल्ली, 3 जून. भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की महत्वपूर्ण बैठक के दौरान देश के बैंकिंग और रियल एस्टेट सेक्टर से ब्याज दरों को लेकर बड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी ने स्पष्ट कहा है कि वर्तमान आर्थिक स्थिति में रेपो रेट को स्थिर रखना ही सबसे उचित निर्णय होगा.

सेट्टी के अनुसार, भारत की आर्थिक वृद्धि दर और महंगाई के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है. उन्होंने कहा कि आरवीआई. ग्रोथ अनुमान लगभग 6.6 प्रतिशत से 6.9 प्रतिशत के बीच रह सकता है, जबकि महंगाई 4.6प्रतिशत से 4.7 प्रतिशत के दायरे में रहने की संभावना है. ऐसे में किसी भी तरह का ब्याज दर परिवर्तन अर्थव्यवस्था के संतुलन को प्रभावित कर सकता है. उन्होंने यह भी बताया कि यदि भविष्य में महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई के पास दरें बढ़ाने का विकल्प मौजूद है, लेकिन अभी ऐसा कदम बैंकिंग सेक्टर के लिए जटिलता पैदा कर सकता है. खासकर डिपॉजिट और लोन दरों के बीच असंतुलन बैंकों के मार्जिन पर दबाव डाल सकता है. वर्तमान में क्रेडिट ग्रोथ 13-15 प्रतिशत के स्तर पर बनी हुई है, जबकि डिपॉजिट ग्रोथ केवल 10-11 प्रतिशत के बीच है. ऐसे में अगर रेपो रेट बढ़ाया जाता है तो बैंकों को जमा पर भी अधिक ब्याज देना होगा, जिससे उनकी लागत बढ़ जाएगी. दूसरी ओर रियल एस्टेट सेक्टर ने भी रेपो रेट में स्थिरता की मांग की है.

5 प्रमुख बातें

- एसबीआई चेयरमैन ने रेपो रेट स्थिर रखने की वकालत की.
- जीडीपी ग्रोथ 6.6 प्रतिशत-6.9 प्रतिशत और महंगाई 4.6प्रतिशत-4.7प्रतिशत अनुमानित.
- क्रेडिट ग्रोथ डिपॉजिट से तेज, बैंकिंग सिस्टम पर दबाव.
- रियल एस्टेट सेक्टर ने भी ब्याज दर स्थिरता की मांग की.
- आरबीआई एमपीसी बैठक के फैसले पर बाजार की नजर टिकी.

सोना बेचने की रिपोर्टों का आरबीआई ने किया खंडन

मुंबई, 03 जून.रिजर्व बैंक ने विदेशी मीडिया में आयी उन रिपोर्टों का जोरदार खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि केंद्रीय बैंक ने विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट को रोकने के लिए भारी मात्रा में सोना बेचा है. केंद्रीय बैंक ने बुधवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि ये रिपोर्ट सही नहीं हैं. उसने कहा कि वह हर महीने उसके पास पड़े भौतिक सोने के आंकड़े जारी करता है. साथ ही स्पष्ट किया गया है कि आज की तारीख में भी स्वर्ण भंडार 880.52 टन पर अपरिवर्तित है, जितना मई में जारी अप्रैल महीने की रिपोर्ट में था. बताया गया था कि 03 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में केंद्रीय बैंक के सोने के भंडार में 180 किलोग्राम का इजाफा हुआ था. यह मार्च के 880.34 टन से बढ़कर 880.52 टन पर पहुंच गया था.

हरित ऊर्जा क्षेत्र में 44 लाख रोजगार सृजन क्षमता

नई नौकरियों में लगभग 43 प्रतिशत हिस्सेदारी रहेगी

लगभग 51 गीगावाट सौर और पवन ऊर्जा क्षमता हासिल की

नई . दिल्ली, 03 जून. देश का 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत निर्धारित उद्देश्य आने वाले समय में 44 लाख से अधिक रोजगार सृजित कर सकते हैं. काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर और नेचुरल रिसोर्सेज डिफेंस काउंसिल इंडिया के एक नये अध्ययन में यह तथ्य सामने आया है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि रूफटॉप सोलर सबसे बड़ा रोजगारदाता होगा, जिसकी कुल अनुमानित नयी नौकरियों में लगभग 43 प्रतिशत हिस्सेदारी रहेगी। ड्राइविंग एनर्जी ट्रांजिशन- वर्कफोर्स, स्किल्स, एंड जेंडर इन इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर नाम से जारी यह रिपोर्ट नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तकनीकी मार्गदर्शन में तैयार किया गया है. यह वर्ष 2024-25 में सौर, पवन, जैव ऊर्जा और जलविद्युत क्षेत्रों की कंपनियों के बीच किये गये एक प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित है.

इस अध्ययन ने विभिन्न स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों और व्यवसायीकरण वाले चरणों में कर्मचारियों की जरूरत का आकलन करने के लिए नया पूर्णकालिक रोजगार गुणांक तैयार किया है। इसके जरिये उपकरणों के विनिर्माण, परियोजनाओं की स्थापना और संचालन में आने वाले प्रत्यक्ष रोजगार का आकलन किया गया है.

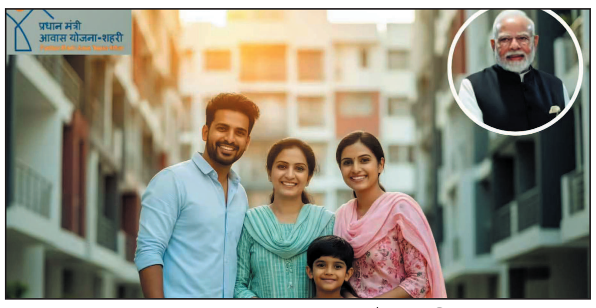

आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार से मजबूत हुआ मध्य वर्ग

नई दिल्ली, 03 जून. एक समय भारत के मध्य वर्ग को उसके सतर्क खर्चों, सीमित विकल्पों और छोटी महत्वाकांक्षाओं से पहचाना जाता था. आज यह वास्तविकता बदल चुकी है. बढ़ती आय, डिजिटल पहुंच और फैलते अवसरों के साथ ही आकांक्षाएं उपलब्धियों में बदल रही हैं.

भारतीय समाज का यह तबका सरकार के समर्थन से लगातार सशक्त हो रहा है. वर्ष 2014 से आयकर छूट सीमाओं में रिकॉर्ड वृद्धि से लेकर जीएसटी सुधारों तक से उसकी बचत और खर्च करने योग्य आय बढ़ी है. अब यह मध्य वर्ग ज्यादा आत्मविश्वास के साथ सशक्त होकर भारत की विकास गाथा के केंद्र में खड़ा है.

मध्य वर्ग की परिभाषा क्रय शक्ति, शिक्षा के स्तर, सामाजिक सेवाओं और धन की अवधारणा के हिसाब से विभिन्न देशों के लिए अलग-अलग है. इस संबंध में विश्व बैंक के पैमाने को व्यापक तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. विश्व बैंक प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर हर वर्ष अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण करता है. वित्त वर्ष 2026 के लिए देशों की आय का वर्गीकरण इस प्रकार है-

1. निम्न आय: 1135 डॉलर या इससे कम
2. निम्न मध्य आय: 1136 डॉलर से 4495 डॉलर तक
3. उच्च मध्य आय: 4496 डॉलर से 13935 डॉलर तक
4. उच्च आय: 13935 डॉलर से अधिक
5. यह वर्गीकरण वैश्विक अर्थव्यवस्था के अंदर मध्य वर्ग आय समूहों के निर्धारण के लिए फ्रेमवर्क मुहैया कराता है.

2010 में विश्व में मध्य वर्ग की आबादी का ज्यादातर हिस्सा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) की अर्थव्यवस्थाओं में रहता था मगर इसमें तेजी से बदलाव आया है. वर्ष 2009 और 2017 के बीच मध्य वर्ग की आबादी 1.8 अरब से ब?कर 3.5 अरब हो गई है. इसका लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा मुख्यत: भारत और चीन समेत एशिया में है. वर्ष 2011 और 2019 के बीच भारत के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 53 प्रतिशत का इजाफा हुआ.

एमपी-सीजी में जियो का नया रिकॉर्ड

मोबाइल उपभोक्ता 5 करोड़ के बेहद करीब, ब्रॉडबैंड ग्राहकों का आंकड़ा 20 लाख पार

भोपाल/रायपुर, 03 जून. रिलायंस जियो ने मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ टेलीकॉम सर्किल में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है. सर्किल में कंपनी के मोबाइल ग्राहकों की संख्या 5 करोड़ के बेहद करीब पहुंच गई है, वहीं ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं का आंकड़ा 20.3 लाख से अधिक हो गया है.

टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, जियो इस क्षेत्र में शीर्ष पर बना हुआ है. अकेले अप्रैल महीने में मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ में जियो से 3.5 लाख नए मोबाइल ग्राहक जुड़े. इसी अवधि में एयरटेल ने लगभग 1 लाख और बीएसएनएल ने करीब 10 हजार नए मोबाइल ग्राहक जोड़े. सर्किल में सभी कंपनियों के कुल मोबाइल ग्राहकों की संख्या 8.6 करोड़ से अधिक है. बाजार हिस्सेदारी के मामले में भी जियो का दबदबा बरकरार है; मोबाइल सेवाओं में जियो की बाजार हिस्सेदारी 58.1 प्रतिशत और ब्रॉडबैंड सेवाओं में 61 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है. ग्राहकों की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए जियो अपने 5 प्रतिशत नेटवर्क का लगातार विस्तार कर रहा है. बेहतर कवरेज और तेज स्पीड के कारण जियो के 5प्रतिशत नेटवर्क पर डेटा ट्रैफिक में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है. इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हाल ही में रायपुर में आयोजित आईपीएल मैचों के दौरान भी देखा गया, जहां भारी डेटा उपयोग के बावजूद जियो नेटवर्क और जियोहॉटस्टार सेवाओं ने निर्बाध प्रदर्शन किया.

मात्र 200 में एंटरटेनमेंट पैक और क्लाउड स्टोरेज

जियो ने ग्राहकों के मनोरंजन के लिए हाल ही में आकर्षक एंटरटेनमेंट पैक लॉन्च किए हैं. इसके तहत उपभोक्ता मात्र रुपए 200 में 15 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, 1000 से ज्यादा टीवी चैनल और 30 जीबी डेटा प्राप्त कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त, व्यवसायों के लिए जियो ने इनोवेटिव मैनेज्ड वाई-फाई समाधान पेश किए हैं, जिनकी विशेषता यह है कि ग्राहकों को किसी प्रकार के शुरुआती निवेश या महंगे उपकरण खरीदने की आवश्यकता नहीं होती. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में बढ़ते खर्च को देखते हुए जियोपीसी एक प्रभावी, किफायती और क्लाउड-आधारित कंप्यूटिंग समाधान के रूप में उभर रहा है.

भोपाल में पहला कॉन्टिनेंटल प्रीमियम ड्राइव स्टोर का उद्घाटन

भोपाल, 03 जून. दुनिया की प्रमुख प्रीमियम टायर निर्माता कंपनी, कॉन्टिनेंटल टायर्स ने भोपाल में अपनी पहली कॉन्टिनेंटल प्रीमियम ड्राइव डीलरशिप का उद्घाटन किया है. शारदा टायर एजेंसी द्वारा संचालित यह नया आउटलेट निरुपम एस्टेट फेज 3, साइकिल ट्रैक, भोपाल-462026, मध्य प्रदेश में स्थित है.

यह स्टोर भोपाल में पहली बार प्रीमियम टायर उत्पादों और पेशेवर वाहन देखभाल सेवाओं को लाकर मध्य भारत में कॉन्टिनेंटल की रिटेल पहुंच को मजबूत करता है. 1,100 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला यह नया कॉन्टिनेंटल प्रीमियम ड्राइव आउटलेट भोपाल में एक अत्याधुनिक सुविधा के रूप में विकसित किया गया है, जो कुशल संचालन के लिए उपयुक्त है.

आईटी शेयरों में मुनाफावसूली का तूफान

टीसीएस 8 प्रतिशत तक लुढ़का

नई दिल्ली, 3 जून. भारतीय आईटी शेयरों में हालिया तेज रैली के बाद बुधवार को मुनाफावसूली का दौर शुरू हो गया. इस दौरान टीसीएस का शेयर करीब 8त्न तक गिरकर ?2,236.50 पर आ गया. निवेशकों ने अमेरिकी बाजार में लिस्टेड एडीआरएस की कमजोरी और तकनीकी संकेतों को देखते हुए मुनाफा बुक करना बेहतर समझा.

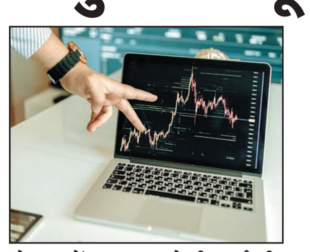

पिछले चार ट्रेडिंग सत्रों में सेक्टर में जबरदस्त तेजी आई थी. निफ्टी इंडेक्स ने करीब 11 प्रतिशत की छलांग लगाई थी. इंफोसिस का शेयर मई 2025 के बाद सबसे बड़ी एकदिवसीय तेजी में 5 प्रतिशत बढ़ा, वहीं टीसीएस ने 6त्न से अधिक की तेजी दिखाई. इसी कारण कई निवेशकों ने मुनाफा बुक किया और शेयरों पर दबाव बढ़ गया.अमेरिका में लिस्टेड इंफोसिस और विप्रो के भी गिरावट देखने को मिली. तकनीकी रूप से निफ्टी इंडेक्स 66.5 पर पहुंच चुका था, जो यह संकेत देता है कि सेक्टर ओवरबॉट हो गया है और थोड़ी गिरावट सामान्य है.आने वाले दिनों में अमेरिकी आईटी खर्च, वैश्विक आर्थिक संकेत और डॉलर की चाल आईटी सेक्टर की दिशा तय करेंगे.

निवेशकों को इन कारकों पर नजर रखनी होगी और गिरावट का सही उपयोग करके पोर्टफोलियो मजबूत करना चाहिए.

अमेरिका की व्यापार कार्रवाई पर भारत ने रखी अपनी बात

नई दिल्ली, 3 जून. भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक मुद्दों को लेकर संवाद का सिलसिला जारी है. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि अमेरिकी व्यापार कानून की धारा 301 के तहत उठाए गए मुद्दों पर दोनों देशों के बीच लगातार बातचीत हो रही है.

यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने भारत सहित कई देशों के खिलाफ व्यापार में कथित असमानताओं और आयात संबंधी उपायों को लेकर जांच पूरी कर ली है. अमेरिका ने अपनी जांच के आधार पर 1974 के अमेरिकी व्यापार अधिनियम की धारा 301 के तहत विभिन्न देशों से आयात किए जाने वाले उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है. हालांकि कुछ उत्पादों को इन प्रस्तावित शुल्कों से बाहर रखने की बात भी कही गई है. इसके अलावा वस्त्र और परिधान क्षेत्र के लिए विशेष व्यवस्था का सुझाव दिया गया है, जिसके तहत सीमित मात्रा में आयात को कम शुल्क दरों पर अनुमति मिल सकती है.

एमएसएमई के लिए हो अलग रेटिंग प्रणाली

नई दिल्ली. इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन की शीर्ष संस्था ईईपीसी इंडिया ने सरकार से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए एक अलग रेटिंग प्रणाली विकसित करने की मांग की है, जो उनके आकार और संचालन की प्रकृति के अनुरूप हो एमएसएमई मंत्रालय को लिखे एक पत्र में ईईपीसी इंडिया के अध्यक्ष पंकज चड्ढा ने बताया कि अपने क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों की तुलना किये जाने के कारण किस प्रकार एमएसएमई को बाहरी रेटिंग एजेंसियों से इन्वेस्टमेंट ग्रेड या ऊंची रेटिंग प्राप्त करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.

समाचार विशेष

अन्नामलाई ने बढ़ाई विजय की टेंशन

दिख सकती है एमजीआर और करुणानिधि जैसी सियासत

नई दिल्ली. तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव भले ही समाप्त हो गए हैं, लेकिन राजनीतिक हलचल अभी भी जारी है. के. अन्नामलाई ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को इस्तीफा सौंप दिया है. हालांकि अमित शाह ने उन्हें जल्दबाजी के लिए रोका है. अन्नामलाई और बीजेपी के बीच काफी समय से मतभेद चल रहे थे.

अन्नामलाई से बीजेपी से इस्तीफे के बाद अब उनके नई पार्टी बनाने की अटकलें भी तेज हो गई हैं. अन्नामलाई के करीबी सूत्रों का कहना है कि अगर वह अपनी खुद की पार्टी बनाते हैं तो तमिलनाडु में दो गैर-द्रविड़ पार्टियों के बीच मुकाबला देखने को मिल सकता है. इन पार्टियों का नेतृत्व राज्य के दो सबसे लोकप्रिय नेता टीवीके के विजय और के. अन्नामलाई करेंगे.

तमिलनाडु की राजनीति में आने वाले समय में थलापति विजय और के. अन्नामलाई के बीच राजनीतिक मुकाबला देखने को मिल सकता है. ऐसे में इनके कुछ समर्थक इनकी तुलना तमिलनाडु के इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में से एक से कर रहे हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन (एमजीआर) और एम करुणानिधि के बीच थी. हालांकि एमजी रामचंद्रन तीन बार मुख्यमंत्री चुनाव जीत चुके हैं और करुणानिधि भी पांच बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं. ऐसे में विजय और अन्नामलाई की दोनों दिग्गज नेताओं से तुलना करना थोड़ी जल्दबाजी समझी जा सकती है.

राजनीति में नाटकीय मोड़

1967 में डीएमके के संस्थापक सीएन अन्नादुरई के कांग्रेस के वर्चस्व को खत्म करने के बाद, तमिलनाडु की राजनीति मुख्य रूप से एमजीआर और करुणानिधि के बीच के मुकाबले में बदल गई थी. डीएमके से अलग होने और एआईडीएमके के गठन के बाद, एमजीआर ने लगातार तीन विधानसभा चुनाव जीते और 1987 में अपने जीवन के अंतिम दिनों तक मुख्यमंत्री बने रहे. एमजीआर की मृत्यु के बाद करुणानिधि सत्ता में लौटे और पांच बार मुख्यमंत्री बने. तमिलनाडु में एक बार फिर अब छह दशक बाद, राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. इस बार तमिलगा वेट्री कषगम (टीवीके) के संस्थापक और अभिनेता से राजनेता बने विजय ने चुनावों में डीएमके और एआईडीएमके दोनों को पीछे छोड़ दिया. दशकों तक तमिलनाडु की राजनीति पर हावी रहने वाली दोनों द्रविड़ पार्टियां अब खुद को एक अपरिचित स्थिति में पा रही हैं.

हिमाचल में कांग्रेस के सामने बड़ी समस्या

शिमला. सब जगह सत्तारूढ़ पार्टियां स्थानीय निकायों के चुनाव जीत रही हैं. पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है. इससे पहले गुजरात में भाजपा ने क्लीन स्वीप किया था. तेलंगाना में ऐसे ही कांग्रेस ने बहुत बड़ी जीत हासिल की थी.

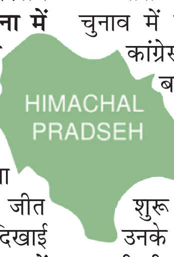

एक केरल अपवाद था, जहां सत्तारूढ़ वाम मोर्चा को कांग्रेस ने हराया था. कांग्रेस की यह जीत विधानसभा चुनाव में भी दिखाई दी. तभी हिमाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस का स्थानीय निकाय चुनाव में हारना उसके लिए बड़ी चिंता की बात है. कांग्रेस अपना गढ़ माने जाने वाले सोलन में भी चुनाव हार गई. वह सिर्फ पालमपुर में जीती है. ध्यान रहे अगले साल के अंत में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है.

उससे पहले स्थानीय निकाय चुनाव में लगे झटके के बाद कांग्रेस की अंदरूनी कलह बढ़ेगी. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को अपने कार्यकाल के शुरू में झटका लगा था. उनके विधायकों ने बगावत कर दी थी और कांग्रेस राज्यसभा का चुनाव हार गई थी. लेकिन बाद में उपचुनाव में सुक्खू ने कांग्रेस को जीत दिलाई और अपना बहुमत मजबूत किया.

भाजपा ने सुहास शिरसाट पर लगाया दांव

मुंबई. महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए औरंगाबाद-जालना निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा ने सुहास शिरसाट को उम्मीदवार बनाकर मराठवाड़ा की राजनीति में बड़ा संदेश दिया है. यह फैसला केवल एक उम्मीदवार की घोषणा नहीं, बल्कि भाजपा की संगठनात्मक प्राथमिकताओं और भविष्य की रणनीति को भी दर्शाता है.

सुहास शिरसाट का राजनीतिक सफर गांव स्तर की राजनीति से शुरू हुआ. उन्होंने सरपंच के रूप में सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की और बाद में संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियां निभाते हुए भाजपा के भरोसेमंद नेताओं में अपनी पहचान बनाई. कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क, संगठन विस्तार और पार्टी कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका ने उन्हें नेतृत्व की नजर में महत्वपूर्ण बनाया. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा ने शिरसाट को उम्मीदवार बनाकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी में जमीनी स्तर पर वर्षों तक काम करने वाले कार्यकर्ताओं को आज भी सम्मान और अवसर मिल सकता है. हाल ही के स्थानीय निकाय चुनावों में औरंगाबाद व जालना जिलों में भाजपा के बेहतर प्रदर्शन ने भी संगठन को मजबूत आधार दिया है.

दूसरी ओर, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए जालना के पूर्व विधायक कैलास गोरंट्याल का नाम भी विधान परिषद की दौड़ में प्रमुखता से लिया जा रहा था. उनके समर्थकों को उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें मौका दे सकती है, लेकिन भाजपा ने संगठननिष्ठ नेता शिरसाट को प्राथमिकता देकर अलग संकेत दिया है.

मराठवाड़ा की राजनीति में बढ़ेगा शिरसाट का कद

उम्मीदवार चयन को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे के प्रभाव और विभिन्न गुटों की राजनीतिक गणित पर भी चर्चा थी. हालांकि अंतिम निर्णय ने यह स्पष्ट कर दिया कि भाजपा नेतृत्व गुटीय समीकरणों से ऊपर उठकर संगठन और राजनीतिक संदेश को प्राथमिकता दे रहा है. विश्लेषकों के अनुसार, शिरसाट की उम्मीदवारी से जमीनी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और संगठन को मजबूती मिलेगी. भाजपा पार्टी ने इस फैसले के जरिए यह भी स्पष्ट किया है कि केवल राजनीतिक वजन या हालिया पार्टी प्रवेश के आधार पर टिकट नहीं मिलेगा. सुहास शिरसाट की उम्मीदवारी से उनका राजनीतिक कद बढ़ना तय माना जा रहा है और आने वाले समय में मराठवाड़ा की राजनीति में उनकी भूमिका और महत्वपूर्ण हो सकती है.

विशेष | **सियासी गलियारों में नई सुगबुगाहट, कब बजेगा चुनावी बिगुल?**

उप्र में 2027 की जगह 2026 में ही चुनाव!

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक नई सुगबुगाहट से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है. उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव तय समय से पहले, यानी 2027 की जगह इसी साल नवंबर-दिसंबर में कराए जा सकते हैं.

दरअसल यह सुगबुगाहट उस वक्त चर्चा में आई, जब राष्ट्रीय जनगणना विभाग ने चुनाव आयोग को सूचित किया है कि फरवरी और मार्च में देश भर में जनगणना का काम युद्धस्तर पर होना है, जिसे केंद्रीय कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है. जनगणना देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक कवायदों में से एक है. ऐसे में जनगणना विभाग ने चुनाव आयोग को पहले ही आगाह कर दिया है कि फरवरी-मार्च के दौरान उनकी पूरी मशीनरी जनगणना के काम में लगी रहेगी.

क्या कहता है चुनाव का नियम?- चुनाव आयोग के नियमों की बात करें तो किसी भी विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने के 6 महीने पहले किसी भी समय चुनाव कराए जा सकते हैं. चुनाव आयोग को इसके लिए संसद से किसी विशेष मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है. यही कारण है कि फरवरी-मार्च के बजाय चुनाव को नवंबर-दिसंबर में खिसकाने की संभावना तलाशी जा रही है. उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 14 मई 2027 को खत्म हो रहा है. संवैधानिक नियमों के मुताबिक, इस तारीख से पहले चुनाव संपन्न कराने के साथ नई सरकार का गठन भी हो जाना अनिवार्य है. पहले ऐसा माना जा रहा था कि फरवरी-मार्च 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन जनगणना के इस नए पेंच की वजह से अब साल 2026 के आखिरी महीनों में ही चुनाव कराने की प्लानिंग की जा रही है.

सियासी दलों में मचा हड़कंप

केंद्र सरकार या चुनाव आयोग ने भले ही अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है. सियासी दलों ने अपनी चुनावी गियर बदल दिए हैं. खबरों के मुताबिक, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी की बैठकों में नेताओं और कार्यकर्ताओं को सीधे हिदायत दी है कि सरकार समय से पहले चुनाव करवा सकती है, इसलिए जमीन पर तैयारी मजबूत रखें. सपा ने दावा किया है कि जनता इस बार बदलाव के लिए तैयार है. भाजपा के अंदर भी वक्त से पहले चुनाव को लेकर गहन मंथन किया जा रहा है. भाजपा को लगता है कि हालिया चुनावों के सकारात्मक मोमेंटम का फायदा उनको यूपी और उत्तराखंड में मिलेगा.